(b) if so, what steps Government propose to take to make adequate and timely supply of cement to Maharashtra?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No specific complaint has been received from the Government of Maharashtra that their projects were held up due to acute shortage of cement in the State. The State Government had, however, represented that the supplies made to them were short of their requirements.

(b) A quota of 16.96 lakh tonnes has been fixed for the State of Maharashtra for the period 1st July, 1973 to 30th June, 1974 on the basis of the average consumption for the past five years. The revised allocation for the 3rd quarter of 1973 which was fixed at 3.82 lakh tonnes, has since been increased by giving them an additional *ad-hoc* quota of 50,000 tonnes for this quarter.

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कच्चे माल की वसूली

1410. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :** क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त के निदेशानुसार पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक से प्राप्त सप्लाई आर्डरों के लिए कच्चे माल की वसूली का दायित्व राज्यों के उद्योग निदेशालयों पर डाला गया है ?

†[**Procurement of raw material for Small Scale Industries**

1410. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI. Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state whether it is a fact that under the directions of the Development Commissioner, Small Scale Industries, the procurement of raw material for the supply orders received from the D.G.S.&D. has been made the responsibility of State Directorate of Industry?]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा इस प्रकार के कोई भी निर्देश नही दिये जाते है।

सम्बन्धित राज्यो के लघु एककों की कच्चे माल की आवश्यक्ताए पूरी करने का उत्तरदायित्व उस राज्य के उद्योग निदेशक पर होता है भले ही इस प्रकार के एककों की पूर्ति के आर्डर सम्भरण और निपटान के महानिदेशालय से अथवा और कहीं से क्यों न मिले हों।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): No such directions are issued by the Development Commissioner (Small Scale Industries)

Directors of Industries are responsible for sponsoring the requirements of raw materials of small scale units in the respective States irrespective of whether such units have achieved supply orders from DGS&D or otherwise.]

उत्तर प्रदेश को आवंटित पैराफिन मोम का कोटा

1411. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 मे केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय को कुल कितने टन पैराफिन मोम आवंटित किया गया ;

(ख) उक्त उद्योग निदेशालय द्वारा पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक से प्राप्त आर्डरों की पूर्ति के लिए विभिन्न एककों को कितने मोम की सप्लाई की गयी ,

†[ ] English translation.